

शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग से निपटान

प्रलिस के लिये:

भारत में रैगिंग के कानूनी परणाम, राघवन समिति, [सर्वोच्च न्यायालय](#)

मेन्स के लिये:

रैगिंग के खतरे को रोकने के लिये UGC के दशा-नरिदेश, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में लगातार परेशान करने वाली रैगिंग की समस्या के मुद्दे ने जादवपुर विश्वविद्यालय में हाल ही में हुई एक घटना के कारण एक बार फिर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

- भारत के [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने विभिन्न मामलों और दशा-नरिदेशों के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान के लिये महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत में रैगिंग विरोधी उपायों की वर्तमान स्थिति:

- रैगिंग को परभाषित करना: सर्वोच्च न्यायालय का परपिरेक्षण:**
 - वर्ष 2001 (वशिव जागृति मिशन) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग की एक व्यापक परभाषा प्रदान की।
 - इसमें रैगिंग को किसी भी अव्यवस्थित आचरण के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें साथी छात्रों को चढ़ाना, उनके साथ अशुचित व्यवहार करना, अनुशासनहीन गतिविधियों में शामिल होना, जिससे झुंझलाहट या मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है या जूनियर छात्रों के बीच डर पैदा होता है।
 - न्यायालय ने यह भी कहा कि रैगिंग के पीछे के उद्देश्यों में अक्सर परपीड़क आनंद प्राप्त करना, नए छात्रों की तुलना में वरिष्ठों द्वारा शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना शामिल होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मुख्य दशा-नरिदेश:**
 - सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेशों में रैगिंग को रोकने तथा उसे संबोधित करने के लिये शैक्षणिक संस्थानों के भीतर प्रोक्टोरल समितियों (Proctoral Committees) स्थापित करने के महत्त्व पर जोर दिया गया है।
 - इसके अलावा इसमें रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट पुलिस से करने की संभावना पर प्रकाश डाला गया है यदि वे असहनीय हो जाती हैं या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाती हैं।
- राघवन समिति और UGC दशा-नरिदेश:**
 - 2009 में सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग मुद्दे पर पुनः विचार किया और इसे व्यापक रूप से संबोधित करने के लिये पूर्व CBI नदिशक आर के राघवन के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की थी।
 - समिति की सफिराशों को बाद में [विश्वविद्यालय अनुदान आयोग \(University Grants Commission- UGC\)](#) द्वारा अपनाया गया/अंगीकृत किया गया।
 - रैगिंग का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिये UGC ने वसितृत दशा-नरिदेश जारी किये जिनका पालन करना विश्वविद्यालयों के लिये आवश्यक था।
 - UGC के दशा-नरिदेश जिसका शीर्षक है, "उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर वनियमन", रैगिंग के कई रूपों पर प्रकाश डालता है, जिसमें चढ़ाना, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुँचाना, हीन भावना उत्पन्न करना और पैसे की ज़बरन वसूली में शामिल होना है।
 - दशा-नरिदेशों में विश्वविद्यालयों को रैगिंग रोकने के लिये सार्वजनिक रूप से अपनी प्रतबिद्धता घोषित करने का आदेश दिया गया है और छात्रों को शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा गया है कि वे ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे।
 - UGC ने रैगिंग के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने की ज़िम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों पर भी डाली है।
 - विश्वविद्यालयों को पाठ्यक्रम-प्रभारी, छात्र सलाहकार, वार्डन और वरिष्ठ छात्रों वाली समितियाँ स्थापित करने का नरिदेश दिया गया था।
 - इन समितियों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिये नए तथा पुराने छात्रों के मध्य बातचीत की निगरानी एवं

वनियमन करने का काम सौंपा गया था।

नोट: यूजीसी ने भी 2016 में लिंग पहचान और यौन अभिविन्यास को रैगिंग के आधार के रूप में मान्यता दी थी।

■ **भारत में रैगिंग के कानूनी नतीजे:**

- हालाँकि रैगिंग को एक वशिष्ट अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, लेकिन [भारतीय दंड संहिता \(Indian Penal Code-IPC\)](#) के विभिन्न प्रावधानों के तहत इसमें दंडित किया जा सकता है।
- उदाहरण के लिये **IPC की धारा 339 के तहत परभाषित रॉगफुल रसिस्टेंट (जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकता है) के अपराधी को एक महीने तक की कैद या पाँच सौ रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है।**
- **IPC की धारा 340 के तहत रॉगफुल कन्फ़ाइनमेंट (जो भी कोई किसी व्यक्ति को गलत तरीके से प्रतर्बिंधित करेगा) के अपराधी को एक वर्ष तक की कैद या एक हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है।**

■ **संबंधित राज्य स्तरीय अधिनियम:**

- कई भारतीय राज्यों ने रैगिंग से निपटने हेतु विशेष कानून पेश किया है।
 - उदाहरण के लिये **केरल रैगिंग निषिध अधिनियम, 1998**; आंध्र प्रदेश रैगिंग निषिध अधिनियम, 1997; असम रैगिंग निषिध अधिनियम 1998 और महाराष्ट्र रैगिंग निषिध अधिनियम, 1999।

आगे की राह

- **रैगिंग विरोधी ठोस उपाय करना:** रैगिंग विरोधी उपायों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये बाहरी विशेषज्ञों, छात्रों और संकाय सदस्यों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक ऑडिट आयोजित करने की आवश्यकता है।
- ये ऑडिट कमियों, सुधार के क्षेत्रों और **सफल प्रथाओं के बारे में अंतरदृष्टि प्रदान कर सकते हैं।**
- इससे प्राप्त **निष्कर्षों का उपयोग शासन की रणनीतियों में सुधार करने और अनुकूलित करने के लिये किया जा सकता है**, जिससे रैगिंग को रोकने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- **डिजिटल रिपोर्टिंग:** कोई छात्र गोपनीय तरीके से रैगिंग की जानकारी साझा कर सके, इसके लिये एक समर्पित रिपोर्टिंग पोर्टल अथवा मोबाइल एप विकसित किया जा सकता है।
- त्वरित हस्तक्षेप सुनिश्चित करते हुए उपयुक्त प्राधिकारियों को बर्ना किसी वलिंग के इसकी सूचना साझा करने की सुविधा इस प्रणाली में शामिल की जा सकती है।
- **सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम:** छात्रों को स्वयंसेवी कार्य, सामुदायिक सेवा और सामाजिक आउटरीच में शामिल करते हुए नियमित रूप से सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। ज़िम्मेदारी और एकता की भावना पैदा करने से इस समस्या के प्रभावी समाधान में मदद मिल सकती है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/combating-ragging-in-educational-institutions>